राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियां

प्रा.डॉ. प्रविण विलास चौगले हिंदी विभाग, कमला कॉलेज, कोल्हापुर।

21वीं सदी को वैज्ञानिक सदी के रूप में जाना जाता है। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के हेतु कठिन से सरल की ओर का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य की उन जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होना भी क्रमप्राप्त है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक व्यापक संकल्पना को प्रस्तावित करने का कार्य शासन की ओर से लिया गया है। जरूरतों की पूर्ति हेतु की इस प्रणाली में उसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, समस्याओं आदि मुद्दों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है।

यूपी 2020 में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के पुनर्गठन, विविध विषयों और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देने सहित विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है। यह प्रणाली एक सर्वसमावेशक और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है। जो छात्रों के बीच में गहन शोध, रचनात्मकता और समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य आदि को पोषित करने का कार्य करती है। सारांश रूप में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु यह प्रणाली कार्यरत है।

हालांकि इन NEP 2020 के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी है। प्राथमिक बाधाओं में से एक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का पैमाना अत्यंत विशाल है जिसके अंतर्गत विविध क्षेत्र, भाषाएं, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भी शामिल होती है। साथ ही एक और बाधा पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र के पुनर्गठन से संबंधित है। NEP 2020 प्रणाली लचीली और बहु दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। छात्रों को उनके रुचि और योग्यता के आधार पर विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि इस बदलाव को लागू करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक कौशल के लिए पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। छात्राओं में ज्ञान की ऊंचाई, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का एकीकरण NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपकरण तक पहुंचने और समानताओं के साथ भारत में डिजिटल डिवाइस प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों की संख्या, उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस विभाजन को बांटना आवश्यक है।

गुणवत्ता की शिक्षा

NEP 2020 शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर भी जोर देता है। एक मजबूत अनुसंधान तंत्र की स्थापना, शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य को साकार करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

हालांकि इन पहलुओं के लिए सावधानीपूर्वक योजना और संसाधन की आवश्यकता होती है। जो मौजूदा वित्तीय बाधाओं के भीतर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एनईपी 2020 की प्रगति और प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र भी आवश्यक है। विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने और योग्य नीतिगत निर्णय लेने के लिए डेटा संग्रह, विश्लेषण और फीडबैक के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है।

अंत में इन एनईपी 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का बड़ा वादा है। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षा परिदृश्य के पैमाने और विविधता, पाठ्यक्रम पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी एकीकरण, डिजिटल विभाजन को बांटने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर काबू पाने के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता होगी। एनईपी 2020 सभी के लिए एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

एनईपी 2020 और इसका कार्यान्वयन मुद्दे और चुनौतियां।

अनुसंधान क्रियाविधि :-

वर्तमान अध्ययन विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक प्रकार है। जो विशेष रूप से द्वितीयक जानकारी पर निर्भर करता है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा वेबसाइट से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की गई है।

एनईपी 2020 और इसका कार्यान्वयन मुद्दे और चुनौतियां :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली को बदलने और 21वीं सदी के शिक्षार्थियों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक रूपरेखा है। सर्वसमावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने की दृष्टि से शिक्षा

को मूलभूत स्तर से उच्च शिक्षा तक क्रांतिकारी बनाना है। हालांकि इस तरह की नीति का सफल कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे एवं चुनौतियां के संदर्भ मे भी सोचना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख में इसी के कार्यान्वयन के दौरान उभरी हुई प्रमुख समस्याएं तथा संभावित समस्याओं के संदर्भ में विचार करने वाले हैं।

राज्य स्तर पर कार्यान्वयन :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रमुख चुनोतियों में से एक भारत के विभिन्न राज्यों के बीच तैयारियों और क्षमताओं का अलग-अलग स्तर है। नीति में व्यापक दिशा- निर्देशों की रूपरेखा दी गई है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करता है कि वह अपनी शिक्षा प्रणालियों को उसी के अनुसार ढाले और सँरेखित करें। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, साथ ही आवश्यक संसाधनों का आवंटन, कठिनाई के संभावित क्षेत्र हो सकते हैं।

पाठ्यचर्या और शैक्षणिक बदलाव :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक शिक्षा पद्धति से अधिक समग्र और उन्मुख शिक्षा दृष्टिकोण में बदलाव का प्रस्ताव करता है। महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने के कौशल्य को प्रोत्साहित करने के लिए इन पाठ्यक्रम सुधारों को लागू करना और शिक्षण विधियों को अपनाना मौजूदा प्रणाली से महत्वपूर्ण समायोजन कर सकता है। इन विधियों को अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और सीखने के उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च गैप :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों के अंतर को देखना आवश्यक है। कई स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।इस के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोशिश होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

अध्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक बदलाव को बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास की आवश्यकता पर जोर देती है। हालांकि लाखो अध्यापकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बड़े पैमाने पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना करने के लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्था और निजी संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। अध्यापकों के लिए निरंतर समर्थन और सलाह आवश्यक होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल को प्राप्त कर सकें।

प्रौद्योगिकी का एकीकरण :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत शिक्षा को सक्षम करने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देती है। हालांकि भारत में डिजिटल डिवाइस इस पहलू के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई समस्याएं है। कई छात्र, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र उपकरणों तक पहुंच और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी रखते हैं। इस खाई को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश, किफायती उपकरणों तक पहुंच और दूरदराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

आकलन और मूल्यांकन :-

यह नीति पारंपरिक मूल्यांकन पद्धति पर आधारित ना होकर नए मूल्यांकन विधियों की वकालत करती है। हालांकि, नए मूल्यांकन मॉडल में संक्रमण उचित मूल्यांकन ढाँचे को डिजाइन करने, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने और मूल्यांकन के लिए मानकीकृत मानदंड विकसित करने के संदर्भ में चुनोतियाँ पेश करता है। मूल्यांकन प्रणाली में महत्वपूर्ण सोच, समस्या को सुलझाने के कौशल, और रचनात्मकता के पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

नीति समन्वय और कार्यान्वयन निगरानी :-

विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करना और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी करना एक जटिल कार्य है। सफल नीति कार्यान्वयन के लिए सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, अध्यापकों और अभिभावकों के बीच प्रभावित सहयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। चुनौतियों का समाधान करने, आवश्यक समायोजन करने और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन, प्रतिक्रिया तंत्र और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है।

समावेशीता और इक्विटी :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा तक समान पहुंच के महत्व पर जोर देता है। जिसमें हाशिए पर रहनेवाले और वंचित समूह भी शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि नीति के लक्षणों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों सहित विविध पृष्ठभूमि के छात्रों तक पहुंचना, भाषा, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और सांस्कृतिक अंतरों की बाधाओं पर काबू पाने के लिए व्यापक योजना और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। यह कुछ चुनौतियां और मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए दौरान उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की क्षमता है। हालांकि सफल कार्यान्वयन के लिए कई मुद्दों और चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है - बुनियादी ढांचे और संसाधनों की खाई को दूर करना, व्यापक अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, मूल्यांकन विधियों की कल्पना करना और नीति समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करना प्रमुख क्षेत्र हैं। जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सभी हितधारकों से निरंतर प्रयास और भारत में शिक्षा को बदलने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। सामूहिक प्रयासों से भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और भविष्य के लिए तैयार पीढ़ी का निर्माण भी कर सकता है।

संदर्भ :-

1. बी. वेंकटेश्वरलू (2021), एनइपी 2020 का एक महत्वपूर्ण अध्ययन : मुद्दे, दृष्टिकोण, चुनौतियाँ, अवसर और आलोचना, इंटरनेशनल जर्नल आफ मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, आईएसएसएन : 2277-7881,पीयर रिव्यूड एंड जर्नल : वॉल्यूम :10, अंक :2(5), पीपी-191-195 ।

2. डॉ. चेतना वी. डोंगलीकर (2023), राष्ट्रीय शिक्षा की चुनौतियां और अवसर उच्च शिक्षा से पहले नीति 2020, लक्ष्मी पुस्तक प्रकाशन, सोलापुर, पीपी -20-23 ।

3. डॉ. मारिया फातिमा डिसूजा (2022), नई शिक्षा नीति 2020 गोवा के विशेष संदर्भ में समीक्षा और कार्यान्वयन, नोशन प्रेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु।